promotion of teachers from lower post to the next promotional post i.e. from Primary School Teachers to Trained Graduate Teachers and Trained Graduate Teachers to Post Graduate Teachers etc. the benefit of F.R 22-C is available to teachers.

Introduction of microlight aircraft in the country

738. SHRI SHAMIM HASHMI: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Aero Club of India proposes to introduce micro-light aircraft in the country despite serious objections raised by the security agencies and that the Club has already contacted for twenty-four such aircraft of which consignment kits for twelve aircraft has already arrived, even though the controversy regarding its use remains unsettled; and

(b) if so, what is Government reaction in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI SHIVRAJ PATIL): (a) and (b) No, Sir. The Directorate General of Civil Aviation constituted a Committee to look into all aspects of registration, manufacture and operation of microlight aircraft in the country The report of the Committee was forwarded to the Bureau of Civil Aviation Security, the Air Headquartars and the Ministry of Home Affairs. These agencies have not objected to the operation of microlight aircraft but have made certain suggestions considering the security aspects involved in the operation of microlight aircraft.

पंजाब विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा आन्दोलन

739. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किये गये वेतनमानों को लागू किये जाने के लिये एक आन्दोलन छेड़ दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पंजाब में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किये गये वेतनमानों को लागू न किये जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. साहो) : (क) पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों के कार्यान्वयन के लिये पंजाब के विश्वविद्यालयों के अध्यापकों द्वारा कोई आन्दोलन नहीं किया गया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पंजाब सरकार ने जनवरी, 1988 में जारी किये गये अपने आदेशों द्वारा जनवरी 1986 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान लागू कर दिये हैं ।

गैर-सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को ढोने के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बसों का किराये पर दिया जाना

740. **श्री राम नरेश यादव :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम द्वारा गैर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को ढोने के लिये प्रति दिन बसें किराये पर दी जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो सितम्बर, 1988 की समाप्ति तक विद्यालयों को कुल कितनी बसें दी गई थी एवं इन बसों को इन विद्यालयों के लिये कितने समय तक के लिये आवंटित किया गया था तथा इस अवधि में वे कितने ट्रिप किया करती थी और प्रत्येक

ट्रिप से दिल्ली परिवहन निगम को क्या आर्थिक प्राप्ति होती थी ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इन विद्यालयों की प्रबंध समितियां विद्यार्थियों से दिल्ली परिवहन निगम को उनके भुगतान की अपेक्षा अधिक धनराशि प्राप्त करती थी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) दिल्ली परिवहन निगम अव्यस्त समय के दौरान छात्रों को लाने ले-जाने के लिये सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों को भाड़े पर अपनी बसें दे रहा है ।

(ख) 30-9-1988 की स्थिति के अनुसार स्कूलों को भाड़े पर दी गई बसों की संख्या 705 थीं । स्कूलों के अवकाशों को छोड़कर शैक्षिक वर्ष के आधार पर भाड़े पर बसें दी जाती हैं ।

बसें किलोमीटर आधार पर भाड़े पर दी जाती है और कि.मी. विभिन्न स्कूल ड्यूटियों के लिये ट्रिपों के अनुसार अलग-अलग होदे है । पिछले छह महीनों के दौरान स्कूल चार्टर पर बसों से हुई आय निम्नलिखित है:--

	(लाख रु०)
अप्रैल, 1988	26.73
मई, 1988	12.42
जून 1988	0.06
जुलाई, 1988	20.77
अगस्त, 1985	30.36
सितम्बर, 1988	28.74

(ग) विभिन्न स्कूलों द्वारा छात्रों से गई राशि के संबंध में दिल्ली परिवहन को जानकारी नहीं है ।

Unsealing of 30 pages of India Wins Freedom by Abul Kalam Azad

741. SHRI PARVATHANENI UPENDRA:
SHRI A. G. KULKARNI:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the remaining 30 pages of Maulana Abul Kalam Azad's book India Wins Freedom were unsealed recently;

(b) whether Government have received reports that the pages were unsealed authorisedly a few years ago; and

(c) if so, what steps were taken by Government to ascertain the facts to fix responsibilty and to penalise those responsible therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI L. P. SHAHI): (a) Yes, Sir.

(b) The Governrment is aware of reports alleging that the packets containing the Azad papers were unsealed unauthorisedly in 1978.

(c) Careful checks were carried out in 1978 itself, both at the National Archives of India, New Delhi and at the National Library, Calcutta, and it was established beyond doubt that the seals were intact. The Delhi High Court ordered the breaking of the seal only because it was fully satisfied that no tampering had been done. Therefore the question of fixing responsibility and penalising anyone does not arise.

Decision taken during talks with King of Nepal in September

742. SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister and the King of Nepal had discussions on a wide range of issues, including bilateral matters, at New Delhi on September, 30, 1988: